राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 22 | जौनपुर | गुरूवार, 04 सितम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सपा नेता पर शिकंजा

प्रयागराज, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष और कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लंबे समय से फरार चल रहे गुलशन यादव पर अब प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (ष्ठत्र) ने इनाम की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। गुलशन यादव पर हत्या के प्रयास, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट जैसे 53 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मानिकपुर थाना क्षेत्र के मऊदारा गांव निवासी गुलशन यादव पर 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट ने उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसी मामले में वह काफी दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। पहले गुलशन यादव की गिरफ्तारी के लिए आईजी प्रयागराज ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी न हो पाने के कारण सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, संजीव गुप्ता ने इस राशि को दोगुना करते हुए एक लाख रुपये कर दिया। कुंडा कोतवाल अवन कुमार दीक्षित ने पुष्टि करते हुए बताया कि एडीजी जोन द्वारा गुलशन यादव की गिरफ्तारी पर अब एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

सिर्फ आधार कार्ड ही अकेले नागरिकता का सबूत नहीं, एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाणपत्र मानने की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर देखा जा सकता है, न कि इसे नागरिकता के लिए माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे अकेले नागरिकता साबित करने के लिए नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा, हम आधार की स्थिति को न तो आधार अधिनियम से परे बढ़ा सकते हैं और न ही पुट्टस्वामी मामले के फैसले से आगे ले जा सकते हैं। बता दें कि आधार अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि आधार न तो नागरिकता देता है और न ही निवास का अधिकार। साथ ही, 2018 के पुट्टस्वामी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। दरअसल, बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने के बाद राजद समेत कुछ दलों ने आधार को मतदाता पंजीकरण के लिए अंतिम प्रमाण बनाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, आधार पर इतना जोर क्यों? चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि बिहार के कई जिलों में आधार सैचुरेशन 140 प्रतिशत से अधिक है,।

नक्सल विरोधी अभियानों से करोड़ों के जीवन में नया सूर्योदय : अमित शाह

नई दिल्ली , (एजेंसी)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से नई दिल्ली में भेंट की। शाह ने जवानों को सम्मानित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों से साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है। मोदी सरकार का संकल्प है कि हम 31 मार्च, 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। शाह ने कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में वीर जवानों द्वारा शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर

अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगा। मोदी सरकार तब तक चौन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएँ या समाप्त न हो जाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे। गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद हौसले के साथ अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैंप समाप्त किया। शाह ने कहा कि कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के मैटीरियल डंप और सप्लाई चेन को छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने अपने पराक्रम से नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहां के स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए।

सीएए के तहत अब तक केवल तीन को मिली नागरिकता सीएम सरमा ने दी जानकारी

गुवाहाटी, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को खुलासा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत अब तक राज्य में सिर्फ तीन विदेशियों को ही भारतीय नागरिकता दी गई है। यह बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब लंबे समय से यह अटकलें और आशंकाएं लगाई जा रही थीं कि लाखों विदेशी असम में सीएए के जरिए नागरिकता हासिल करेंगे। सरमा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब तक केवल तीन लोगों को असम में सीएए के तहत नागरिकता मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से तीन को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि नौ अभी विचाराधीन हैं। सीएम ने कहा, बहुत शोर मचाया गया कि 20–25 लाख लोग असम में नागरिकता पाएंगे। अब आप ही तय करें कि जब केवल 12 आवेदन आए हैं तो इस पर चर्चा करना कितना प्रासंगिक है। असम में सीएए के पहले लाभार्थी बने 50 वर्षीय दुलोन दास, जिन्हें अगस्त 2024 में भारतीय नागरिकता मिली। वे राज्य में इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति बने।

नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के उन शरणार्थियों को नागरिकता देना है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हों और 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां प्रवेश कर चुके हों। साथ ही, उन्हें भारत में कम से कम पाँच वर्ष का निवास पूरा करना अनिवार्य है। सीएए दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था, लेकिन इसे 11 मार्च 2024 को लागू किया गया, जब इसके नियम अधिसूचित किए गए। केंद्र ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि गैर–मुस्लिम अवैध प्रवासियों के मामलों को फिलहाल विदेशियों के न्यायाधिकरण (एफटीएस) को न भेजा जाए।

सिंगापुर के पीएम वोंग ने वित्त मंत्री सीतारमण से की मुलाकात

सिंगापुर, (एजेंसी)। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। यह मुलाकात नई दिल्ली में हुई, जहां दोनों नेताओं ने

भारत और सिंगापुर के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इस बातचीत का मकसद व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और पर्यावरण जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था। इस दौरान दोनों नेताओं ने इन सभी क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। बता दें कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। उनकी यह यात्रा भारत–सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। बैठक में सिंगापुर की ओर से उनके साथ कार्यवाहक परिवहन मंत्री जेफरी सिओ और विदेश मामलों की राज्य मंत्री गान सिओ हुआंग भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच गहरे और भरोसेमंद संबंधों की पुष्टि करती है। इसके साथ ही सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीतारमण से मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें वित्त मंत्री सीतारमण से दोबारा मिलकर खुशी हुई। उन्होंने हाल ही में हुए भारत–सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के नतीजों और सीमा पार डेटा और पूंजी बाजारों में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री वोंग अपनी तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं।

बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का एलान करे सरकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में भारी बारिश ने इन दिनों तबाही मचाई हुई है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की अपील राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कहा, श्मोदी जी, बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है।

जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपके इस तरफ ध्यान देने और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद की बेहद जरूरत है। हजारों परिवार अपने घर, जिंदगी और अपनों को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, श्मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों, खासकर किसानों के लिए तत्काल एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा श्लोगों को अपने परिवारों को बचाने के लिए संघर्ष करते देखना दुखद है। मोदी जी, लोगों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक विशेष राहत पैकेज तैयार करें पिछले कुछ हफ्तों से देश के कई हिस्सों में लगातार बादल फटने और बाढ़ की खबरें आ रही हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। उफनती नदियों ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है, रेल और सड़क यातायात को ठप कर दिया है और स्कूलों को बंद करना पड़ा है। साल 1988 के बाद पंजाब सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। सतलुज, व्यास और रावी नदियां और मौसमी छोटी नदियां भारी बारिश के कारण उफान पर हैं।

बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलने पंजाब जाएंगे शिवराज सिंह चौहान

पंजाब, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वह गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित परिवारों से मिलने पहुँचेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। चौहान ने ग पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां के साथ भारी बारिश के बीच पंजाब की विनाशकारी स्थिति पर चर्चा की। चौहान ने पोस्ट में कहा कि आज मैंने पंजाब के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के साथ पंजाब में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और विस्तृत

जानकारी प्राप्त की। मैं कल सुबह पंजाब पहुँचूँगा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपने भाइयों और बहनों से मिलूँगा। संकट की इस घड़ी में, केंद्र सरकार पंजाब के भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इससे पहले आज, अमृतसर के अजनाला स्थित गग्गो महल गाँव में लगातार भारी बारिश के बीच बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई। जीरकपुर में भी बारिश की सूचना मिली है, जिससे शहर के कई हिस्सों में हल्का यातायात जाम हो गया है। लगातार भारी बारिश के कारण, राज्य भर के बाँधों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों की सहायता से हबीब के बाँध तटबंध पर मरम्मत कार्य चल रहा है। पंजाब में जारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार सभी स्कूल और कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को ग पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस निर्देश की जानकारी दी और सभी से स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। बैंस ने एक पोस्ट में कहा, ष्माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पंजाब भर के सभी सरकारीध्सहायता प्राप्तध्मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर 2025 तक बंद रहेंगे।

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद पहली जनसुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद वह एक बार फिर बुधवार को जनसुनवाई आयोजित कर रही हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। सीएम की सुरक्षा में इस बार कोई चूक न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने फुलप्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि किसी भी संदिग्ध की पहचान के लिए सीएम के घर के बाहर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) से लैस गाड़ी वहां तैनात रहेगी। इस गाड़ी में इस्राइली सिस्टम लगा हुआ है। इसकी मदद से किसी भी संदिग्ध की पहचान कर उसको पहले से ही रोका जा सकेगा। सीएम आवास की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खुद जिला पुलिस उपायुक्त के अलावा कई एसीपी, इंस्पेक्टर व बाकी स्टाफ भी वहां तैनात रहेगा। सुबह करीब साढ़े आठ बजे से शुरू होने वाली जनसुनवाई जब तक भी चलेगी तब तक पुलिस बल वहां तैनात रहेगा। लोकल पुलिस के अलावा सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी वहां तैनात रहेंगे। पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि सीएम की सुरक्षा को देखते हुए सादे कपड़ों में पुलिस के जवान उनके घर के अंदर व बाहर दोनों जगह तैनात होंगे। यह हर आने–जाने वाले पर पैनी नजर रखेंगे। सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती सीएम आवास पर की गई है। वह महिलाओं पर नजर रखेंगी। अधिकारी ने बताया कि सीएम आवास के पास मेटल डिटेक्टर, पिकेट कमांडो की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि सीएम को जेड श्रेणी की की सुरक्षा प्राप्त है, सीएम की सुरक्षा का जिम्मा उनके पास ही है। सीएम को सुरक्षा कवर देने के लिए सीआरपीएम के जवान भी उनके ईदगिर्द रहेंगे। ऐसा आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि 20 को जनसुनवाई के दौरान गुजरात के राजकोट से आए राजेश भाई खिमजी ने सीएम पर अचानक हमला कर दिया था। खुद को वह डॉग लवर बता रहा था।

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया

हरिद्वार, (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार जिले के बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर क्षतिग्रस्त सड़कों और जलमग्न खेतों से गुजरे। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो रही है। धामी ने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की, उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रुड़की से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रदीप बत्रा, हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल भी मुख्यमंत्री के साथ थे। धामी ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा, ठहरने, भोजन और स्वास्थ्य सेवा के सभी प्रबंध किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सरकार द्वारा यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त भोजन, पानी और दवाओं के साथ राहत शिविर स्थापित किए जाने चाहिए और जिन परिवारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करके मुआवजा प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए। धामी ने कहा कि आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाकर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर
शिक्षकों एवं स्नातक बुद्धिजीवियों
का हार्दिक अभिनंदन

कान्ति सिंह पूर्व एमएलसी
मुख्य प्रशासिका

सुशील कुमार
प्रबन्ध निदेशक

डॉ. एस. पी. सिंह
सांसद
संस्थापक चेयरमैन

लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एण्ड कॉलेजेज़

संपादकीय

उम्मीदों की चिप

भारत ने टेक क्रांति की तरफ बढ़ते हुए पहला पूर्णतरू स्वदेशी 32–बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित कर लिया है। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब इस कामयाबी की साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं। जिनमें से एक पंजाब के मोहाली में स्थित है। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है। भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया–2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। यहां तक कि छोटा–सा देश ताइवान दुनिया के लगभग साठ फीसदी से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहा है। जिसमें करीब नब्बे फीसदी उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। दरअसल, कोविड संकट के बाद आधुनिक तकनीक व उन्नत उपकरणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर होड़ पैदा हो गई है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान–विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिये मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान–विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिये दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति शृंखला को मजबूत बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की दिशा में भारत का एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनिया के लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी क्षेत्र में कामयाबी के लिये भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कंपनियों को संबल देने के लिये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई के तहत दिए जा रहे लाभ के विस्तार के साथ ही, इसके तहत दिये जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओं के लिये केंद्र व राज्यों से प्रोत्साहन के रूप में परियोजना की कुल लागत का सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पचास फीसदी पूंजीगत सहायता दे रही है। वहीं राज्य सरकारें कुल परियोजना लागत का बीस फीसदी प्रोत्साहन दे रही हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है।

वर्दी में फौजी से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक

मोहन

युद्धक्षेत्र से लेकर स्टार्टअप तक, निष्ठा भारत का सबसे ज्यादा अप्रयुक्त संसाधन है। यह ऑपरेशन सिंदूर में साबित भी हुआ। प्रतिवर्ष 70,000 प्रशिक्षित सेवानिवृत्त फौजी देश के अर्थतंत्र में शामिल होते हैं। इस नवीकरणीय पूंजी में कौशल, निर्णय शक्ति छिपी है। एक द्वितीय लाभांश नीति बनाकर इन सेवानिवृत्त दिग्गजों को उन नियोक्ताओं से जोड़ सकते हैं, जो इन्हीं क्षमताओं को ढूंढ़ रहे हैं। भारत की अधिकांश नीतिगत शब्दावली अभी भी सैनिकों की पेंशन को एक 'बोझ' के रूप में वर्णित

करती है। जबकि यह एक गलतफहमी है। जिसे दायित्व कहा जाता रहा है, वह दरअसल एक विलंबित मान्यता है। जिसे लागत कहकर खारिज किया जाता है, वह असल में गणतंत्र के लिए द्वितीय लाभांश है। कुरुक्षेत्र से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, निष्ठा भारत में निरंतर क्रम है, और यह 40 साल उम्र में खत्म नहीं हो जाती। ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा प्रमाण है रू 22 मिनट की सटीकता, 88 घंटे की सतर्कता, और फिर युद्धबंदी। आज की बिखरी विश्व व्यवस्था में बहुत कम राष्ट्र अपने पास इतने बड़े पैमाने का अनुशासन होने का दावा कर सकते हैं। निष्ठा कोई नई नहीं है। इसने 1971 में टैंकों को मेघना नदी पार करवा दी, 2025 में इसी ने दृष्टि की सीमा से परे ठिकानों पर सटीक आयुधों की मार का प्रदर्शन किया। निष्ठा भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक विरासत है। ब्रिटिश हुकूमत ने पेंशन की रूपरेखा एक मान्यता के रूप में नहीं बनाई थी। एक ऐसा बंधन, जो वफादारी को बांधे रखने में पर्याप्त, लेकिन अपने हाल पर छोड़ देने में सदा नाकाफी। आजाद भारत को यह रूपरेखा विरासत में मिली, और अर्थशास्त्रियों ने पेंशन को आर्थिक घाटा व निकासी मान, इस गलती को और पुख्ता किया। लेकिन जिसे हमारे बहीखाते 'पेंशन बोझ' कहते हैं, वह वास्तव में नवीकरणीय पूंजी है रू प्रति वर्ष 70,000 प्रशिक्षित सेवानिवृत्त फौजी, बिना किसी पुनरू उपयोग योजना के, देश के अर्थतंत्र में शामिल होते हैं। उनपर लगे प्रत्येक रुपये में दशकों के कौशल, निर्णय शक्ति और सहनशीलता छिपी है, एक ऐसी पूंजी जिसे कोई अन्य राष्ट्र इतनी आसानी से व्यर्थ जाने देना नहीं चाहेगा। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक के एक लेख में भानु प्रताप ने लिखा है रू 'अग्रणी व्यवसायियों को अक्सर शिकायत रहती है कि देश में कुशल मानव पूंजी की कमी है, हालांकि इसका निर्माण करने को निवेश करने में वे सदा अनिच्छुक रहे।' इस बीच, हर साल हमारा गणतंत्र अपनी सबसे अनुशासित, मिशन को तैयार प्रतिभा को फालतू हुआ मानता आ रहा है, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में कुशल कामगार लाने या पुनः प्रशिक्षण पर अरबों खर्चे जाते हैं। यह अकुशलता नहीं बल्कि औद्योगिक अनदेखी है। सही नीति से स्थिति सुधर सकती है। भारत स्थायी भरोसे की अहमियत समझता हैय यह स्मृति में अंकित है। फिर भी, नीतिगत शब्दावली में, उस भरोसे को का अर्थ अक्सर रोजगार से जोड़ दिया गया है। एक ऐसे लोकतंत्र में, जहां नौकरी ताकत पाने का शॉर्टकट हो, पेंशन को हक जताना मान लिया गया। बेढंगी योजनाएं नौकरी को अनुभव पाने का जरिया और प्रतिज्ञा को अनुबंध के रूप में देखने लगीं। वे भर्ती को व्यापक बनाती हैं और युवा ऊर्जा लेकर आती हैं। जो लोग सेना छोड़ देते हैं, वे समाज में अनुशासन साथ लेकर जाते हैं। किंतु अनुबंध, सोच–समझकर कुछ ऐसा बनाया गया है कि भर्ती होते वक्त से ही सेवानिवृत्ति के लिए भी मानसिक तैयार कर दे। दूसरा लाभांश लंबी सेवा पर निर्भर करता है, जहां प्रतिबद्धता, निर्णय क्षमता और फिर आगे पूंजी के रूप में परिपक्व हो जाती है। दृढ़ता तभी बढ़ती है जब सैनिक वर्दी को अपना घर, सम्मान और कई मामलों में विरासत होने का दावा कर सके। द्वितीय लाभांश की राह लंबी है, यह अनुभव को नवीनीकरण से जोड़ता है, जहां नवोन्मेष करने वाले को अपने लिए बीज मिल सकते हैं। जहां भारत में निष्ठा को बोझ का नाम दिया जा रहा है वहीं दूसरे देशों ने इसे कतई त्याग दिया रू रूस और यूक्रेन फिर से सामूहिक सैन्य भर्ती करने पर निर्भर हो गए हैं–संख्याबल बनाए रखने को अनुभव से समझौता और मारे गये सैनिकों की जगह लेने के लिए नए युवा लाना। पश्चिम एशिया सशस्त्र लड़ाकू गुटों में बंटा हुआ है, जहां निष्ठा अर्जित नहीं, खरीदी जाती है। नतीजन, अंतहीन लड़ाइयां, बरसों खिंचने वाले युद्ध, जिनको केवल बही खातों और हताहतों के आंकड़ों से मापा जाता है। इसके उलट, भारत के पास सेवानिवृत्त फौजी रूपी अनुशासित लाभांश उपलब्ध हैं – बतौर अनाड़ी रंगरूट नहीं, न ही भाड़े के बंदूकधारी, बल्कि उच्च कौशल और निर्णय दक्षता प्राप्त स्त्री–पुरुष। हर साल हजारों सैनिक अपनी पेशेवर क्षमता के चरम पर सेवानिवृत्ति श्रेणी में शामिल हो जाते हैं – अगुवाई करने की दक्षता प्राप्त इंजीनियर, आपूर्ति शृंखला में पारंगत,चिकित्सक, संचार विशेषज्ञ आदि। गणतंत्र इस पूंजी को आकार देने में दशकों लगा देता है, लेकिन फिर इनके पुनरू उपयोग की कोई योजना न बनाकर, इसको व्यर्थ जाने देता है। फौज में आपूर्ति शृंखला में काम चुका एक पूर्व सैनिक इस क्षेत्र में कमियां दूर कर सकता है। फील्ड अस्पतालों में प्रशिक्षित नर्सिंग सहायक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को विस्तार दे सकती है। उन्नत प्रणालियों में कुशलता अर्जित कर चुके एक तकनीशियन को सेवानिवृत्ति उपरांत अक्सर बैंक गार्ड लगाकर उसका सारा अनुभव बेकार जाने दिया जाता है। फौजियों से बनी प्रादेशिक सेना को भी पुनर्कल्पित कर,नागरिक सुरक्षा में व्याप्त कमियों को पाटा जा सकता है। ये पुनर्निवेश की बाट जोहते लाभांश हैं। गणतंत्र पहले से ही ऐसे सैन्य कौशल गढ़ता आया है जो किसी स्टार्टअप अर्थतंत्र में सबसे अधिक मांग वाली क्षमताओं को प्रतिबिंबित करते हैंरू तनाव में भी सही निर्णय क्षमता, बड़े पैमाने पर रसद पहुंचाना, फील्ड में तकनीक उपयोग, विपरीत परिस्थितियों में ध ीरज कायम रखना और अनिश्चितता भरे माहौल में दल की नेतृत्व क्षमता। ये कोई कपोल–कल्पित अवयव नहीं हैंय बल्कि यूनिकॉर्न (बिलियन डॉलर की कंपनी) बनाने में जरूरी डीएनए हैं। एक द्वितीय–लाभांश नीति परस्पर जरूरतों का मिलान कर करके, सेवानिवृत्त दिग्गजों को उन नियोक्ताओं से जोड़ सकती है, जो इन्हीं क्षमताओं को ढूंढ़ रहे हैं, मसलन, साइबर, एआई, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति शृंखला, स्वच्छ ऊर्जा आदि क्षेत्र में। भारत जिन्हें अब व्यर्थ जाने दे रहा, वह अरबों डॉलर के उद्यमों की अगली लहर के लिए कच्चा माल है। पश्चिमी सेवानिवृत्त फौजी साइबर सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला और एआई क्षेत्र में यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी कर चुके हैं, जिन्होंने रणभूमि में समस्या आने पर त्वरित सही निर्णय लेने में अर्जित अपने अनुभवों को अरबों डॉलर कमाने में बदल दिया।

पीड़ितों की मदद हेतु हमारी जवाबदेही

पंजाब में बाढ़ का संकट बेहद गंभीर है। फिलहाल चुनौती जीवन रक्षा की है। पीड़ितों के लिए भोजन व साफ पानी की है। उनको राहत देना व पुनर्वास प्राथमिकता हो। पीड़ितों को समय रहते मुआवजा मिले। बाढ़ के बाद की चुनौतियों के मुकाबले को सरकार व समाज मिलकर काम करें। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, जहां गांव जलमग्न हो गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं और खेतों में फसल की जगह बालू भर गई है। यह संकट केवल पानी उतरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में समस्याएं और गहराएंगी। इस समय खेती और पशुधन से संपन्न पंजाब में नदियों–नालों में आये उफान के कारण तीन लाख एकड़ से ज्यादा फसली जमीन को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा असर धान, मक्का, सब्जियों और अन्य खरीफ फसलों पर हुआ है। सीमा से लगे गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, फाजिल्का, कपूरथला व आसपास के गांवों में घर, सड़क और दुकानें पानी में डूब गई हैं। अब तक करीब 2.56 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित पंजाब में भारी तबाही के चलते बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की आवश्यकता है। भोजन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन साफ पेयजल की भारी कमी है क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं और गंदा पानी पीने से हैजा फैलने का खतरा है। रोज लाखों बोतल पानी, बिना बिजली वाले फिल्टर, बड़े आरओ, इन्वर्टर, बैटरी, मोमबत्तियां, माचिस और छोटे जनरेटर की तत्काल जरूरत है क्योंकि बिजली बहाल होने में लंबा समय लगेगा। साथ ही महामारी रोकने के लिए फिनाइल, क्लोरीन पाउडर, मच्छर मारने की दवाइयों व क्रीम की भी तुरंत आवश्यकता है। बारिश थमने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी, कीचड़, मलबा और मरे जानवरों का निस्तारण करना। इसके लिए बड़े पंप, जेसीबी, डंपर, ईंधन, सफाई उपकरण व सुरक्षात्मक सामान की तत्काल जरूरत है। सरकारी तंत्र के पास इतनी मशीनरी तुरंत उपलब्ध नहीं होती, इसलिए समाज के लोगों को चाहिए कि वे ऐसे उपकरण राज्य सरकार को भेंट करें, ताकि पुनर्वास कार्य तेजी और प्रभावी ढंग से हो सके। राहत कार्यों में बड़ी व्यवस्थाओं के साथ–साथ पीड़ित आम लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मधुमेह, ब्लडप्रेशर, थायराइड जैसे रोगियों को नियमित दवाएं चाहिए, जो बाढ़ में नष्ट हो चुकी हैं। मानसिक तनाव और सीमित राहत सुविधाओं से अव्यवस्थित लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में दवाइयां, पेयजल, डेटॉल, फिनाइल, क्लोरिन टैबलेट्स, संक्रमण व बुखार की दवाएं, ग्लूकोज, सेलाइन जैसी चीजें तत्काल आवश्यक हैं। पुराने कपड़े या अनाज जैसी चीजें फिलहाल उपयोगी नहीं होंगी संपन्न लोगों को आगे बढ़कर पुनर्निर्माण में योगदान देना होगाकृजैसे दूरदराज के गांवों के लिए सीमेंट, लोहा जैसी निर्माण सामग्री भेजना। करीब ढाई लाख लोग पूरी तरह बेघर हो गए हैं, बाजार–वाहन तबाह हो चुके हैं। ऐसे में बीमा दावों का त्वरित और सही निपटारा बड़ी राहत हो सकता है। लेकिन राज्य मशीनरी खुद संभलने में व्यस्त है, इसलिए शिक्षित स्वयंसेवकों की जरूरत है जो नुकसान का सही आकलन कर, बीमा कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव बना सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावितों तक पहुंचा सकें। बाढ़ के बाद जीवन को फिर से पटरी पर लाने में सबसे बड़ी बाधा होगी।

..... विविध .....

दवा बिन दर्द का राहतकारी उपचार

दुनिया में फिजियोथैरेपी को दर्द को मैनेज करने के प्रभावी तरीके व राहतकारी उपचार के रूप में मान्यता मिल रही है। फिजियोथैरेपी दर्द मुक्ति का पैरा मेडिकल जरिया है, जिसमें दवाओं का या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता या मामूली ही होता है। फिजियोथैरेपी से हम कई तरह के साइड इफेक्ट से बचे रहते हैं। इसी कारण नयी पीढ़ी का भरोसा भी

फिजियोथैरेपी पर बढ़ रहा है।

रेखा देशराज

पहले दर्द को लेकर आम तौर पर सोच होती थी कि इससे छुटकारा पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन उन्नत हुई मेडिकल सुविधाओं के तहत आज दर्द को आसानी से मैनेज किया जाता है। लेकिन हाल के दशकों में लोगों ने तब एक और बड़ी समस्या महसूस की, जब पाया कि दर्द को दवाओं से मैनेज करने का नतीजा यह होता है कि वह साइड इफेक्ट के जरिये हमें परेशान करता है। यही कारण है कि इन दिनों पूरी दुनिया में फिजियोथैरेपी को दर्द की सबसे कारगर औषधि के रूप में मान्यता मिल रही है।

साइड इफेक्ट नहीं

आज की अत्यधिक व्यस्त जीवनशैली में दर्द हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया हैय क्योंकि कामकाज में बढ़ती मशीनी सुविधाओं के कारण व्यस्त और कार्यरत रहते हुए भी शारीरिक रूप से हमारी गतिविधियां सुस्त होती हैं। इसलिए बिना नियमित एक्सरसाइज किए, शरीर को जरूरी सक्रियता नहीं मिलती, जिस कारण ज्यादातर लोग शरीर के किसी न किसी हिस्से के दर्द से अकसर पीड़ित रहते हैं और इस दर्द से बचने के लिए अगर वे ज्यादा से ज्यादा दवाओं पर निर्भर रहते हैं, तो इसके कई तरह के साइड इफेक्ट परेशान करते हैं। जबकि फिजियोथैरेपी दर्द मुक्ति का एक ऐसा अर्धचिकित्सीय जरिया है, जिसमें दवाओं का या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता या बहुत मामूली ही होता है। इस कारण फिजियोथैरेपी से हम कई तरह के साइड इफेक्ट से बचे रहते हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में खासकर मॉर्डन कंप्यूटर लाइफस्टाइल से घिरे युवा, शरीर के विभिन्न किस्म के दर्दों से राहत पाने के लिए दवाओं से ज्यादा फिजियोथैरेपी पर भरोसा करते हैं।

फिजियोथैरेपी के महत्वपूर्ण होने की वजह

अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है, तो सवाल है फिजियोथैरेपी क्यों चुननी चाहिए? इसकी पहली वजह तो यह है कि फिजियोथैरेपिस्ट दर्द को प्रबंधित करने में बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित होते हैं। यही कारण है कि उन्हें मूवमेंट डिसऑर्डर के इलाज में विशेषज्ञ माना जाता है। वे हमें दर्द से छुटकारा दिलाने और इसे अच्छी तरह से मैनेज करने का सबसे वैज्ञानिक और शरीर के अनुकूल तरीका सिखाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिक ढंग से डिजाइन किया हुआ तरीका, चोट से उबरने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शारीरिक व्यायाम को बेहद वैज्ञानिक तरीका प्रदान किया जाता है, जो उपचार का जरिया बन जाता है।

फिजियोथैरेपिस्ट– भरोसेमंद उपचारक

फिजियोथैरेपिस्ट आपकी चोट का, आपकी दर्द की स्थिति का, गहराई से अध्ययन करके आपके व्यक्तिगत शरीर के अनुरूप रिकवरी योजना सुझाते हैं। जबकि मेडिकल प्रक्रिया में रोग के सैद्धांतिक उपचार पर जोर होता है, वहां आपके व्यक्तिगत चोट या शारीरिक संरचना का उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जितना किसी दवा के सैद्धांतिक रूप से विकसित करने के सिद्धांत पर जोर होता है। फिजियोथैरेपी में किसी अन्य की बजाय आप खुद अपने उपचारक होते हैं। फिजियोथैरेपिस्ट तो एक तरह का निर्देश देता है और आप अपने शरीर की अनुकूल सहनशक्ति के मुताबिक उसका पालन करते हैं। इसमें खास तौरपर आपकी प्रकृति और प्रगति दोनों को ट्रैक किया जाता है। फिजियोथैरेपिस्ट को दरअसल दर्द नहीं बल्कि दर्द पैदा करने वाली स्थितियों का इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यही वजह है कि खेल की चोटें, गठिया का दर्द, पीठ का दर्द, सिरदर्द और कई तरह के पुराने और लंबे समय से चले आ रहे दर्दों से राहत फिजियोथैरेपिस्ट दिला पाते हैं। खास तौरपर इसलिए भी कि इस तरीके में ज्यादा सहूलियत और नतीजा मिलता है, क्योंकि इसमें खुद आप अपने दर्द निवारण इलाज में फिजियोथैरेपिस्ट के निर्देशों के मुताबिक शामिल होते हैं। वे आपको सिखा देते हैं कि कैसे स्थितियों का प्रबंधन किया जाए। इसलिए फिजियोथैरेपी के चलते दर्द से छुटकारा पाना आसान होता है।

हर उम्र में हैल्दी रहने को जरूरी है सावधानी का खानपान

आहार से प्राप्त पोषण रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं पोषक तत्व शारीरिक–मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं और बीमारियों से बचाने में भी सहायक हैं। खुराक उम्र, शारीरिक बनावट, दिनचर्या और एक्टिविटीज के हिसाब से बदलती रहती है। इसी संबंध में लखनऊ स्थित एक नामी अस्पताल में न्यूट्रीशनिस्ट डॉ. चेतना बंसल से रजनी अरोड़ा की बातचीत। हमारी मूलभूत जरूरतों में एक आहार, खासकर संतुलित आहार, हमारी स्वस्थ जिंदगी का आधार है। आहार की भूमिका सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। हम जो भी खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। संतुलित भोजन स्वास्थ्य से जुड़ी ढेरों समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और व्यक्ति निरोगी जीवन जी सकता है। आहार से प्राप्त पोषण न केवल रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बल्कि शारीरिक–मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है और बीमारियों से बचाने में सहायक है। लेकिन कई स्थितियों में आहार से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता जिससे कई समस्याएं, रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। डाइट उम्र, शारीरिक बनावट, दिनचर्या और एक्टिविटीज के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए सभी को सही आहार चुनना और उसकी न्यूट्रिशियन वेल्यू को जानना जरूरी है यानी स्वस्थ पोषण के लिए क्या खाया जाए।

डाइट के मानक

विशेषज्ञों के हिसाब से हेल्दी डाइट के फंडे को समझने के लिए कई मानक हैं जिनके आधार पर आहार संयोजन स्वास्थ्यप्रद है– प्लेट को 4 हिस्से में बांटना चाहिए। एक–चौथाई हिस्से में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर अनाज, दूसरे में मौसमी सब्जियां हों तीसरे में प्रोटीन फूड हो और चौथे हिस्से में सलाद, मौसमी फल और दूध से बनी चीजें होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट,लंच और डिनर में यह मानक लागू किया जाना चाहिए। न्यूट्रीशन पिरामिड से तय किया गया है कि अच्छी डाइट में सबसे ज्यादा भाग फल–सब्जियां और साबुत अनाज होते हैं। इसके बाद दालें, बीन्स सोया आते हैं। इसके बाद नट, बीज, बीन्स व मांसाहारी भोजन को रखा गया है। फिर कम वसा वाला दूध और दूध से बने पदार्थ आते हैं। आखिर में रिफाइंड ऑयल, फास्ट फूड और रिफाइंड अनाज कम से कम मात्रा में लें।

ऐसा हो संतुलित आहार

आहार विशेषज्ञों की मानें तो हमें ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच मध्यवर्गीय व्यक्ति की तरह और डिनर गरीब की तरह खाना चाहिए। मॉडरेशन में संतुलित आहार लें। हरेक मील में सभी फूड ग्रुप का सेवन करना जरूरी है। यानी खाने की प्लेट में एनर्जी गिविंग (कार्बोहाइड्रेट), बॉडी बिल्डिंग (प्रोटीन, कैल्शियम) और प्रोटेक्टिव (विटामिन और मिनरल) फूड, फाइबर और पानी सही मात्रा में शामिल करने चाहिए। आहार में माइक्रो (विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड) और मैक्रो (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट) न्यूट्रेंट्स समुचित मात्रा में शामिल करना जरूरी हैं। इनकी कमी से कुपोषण, एनीमिया के अलावा कई बीमारियां होने की आशंका रहती है।

सही पोषण हर उम्र में

बचपन से लेकर हर उम्र के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। अलग–अलग मानक तय किए गए हैं जिनके अनुसार भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। बचपन से अच्छी डाइट फॉलो करना हमें व्यस्क होने और वृद्धावस्था में भी कई बीमारियों से दूर रखता है। अमूमन एक व्यस्क व्यक्ति को रोजाना 2000–2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए 10 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत होती है। शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए महिलाएं और बच्चे आयरन–कैल्शियम रिच डाइट लें।

बच्चे की खुराक

वैज्ञानिकों के अनुसार, मां का दूध विशेषकर डिलीवरी के तुरंत बाद वाला 'कोलस्ट्रम' नवजात शिशु के लिए अमृत के समान होता है। इसमें

मौजूद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा जैसे पोषक तत्व जहां शिशु के विकास में सहायक होते हैं वहीं इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, लिंफोसाइट, लैक्टोफेरिन, बाइफीडिस जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व उसके लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं। ये तत्व शिशु के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। छह महीने के बाद शिशु को मां के दूध के अलावा सप्लीमेंटरी फूड भी देने शुरू कर देने चाहिए। टॉप फार्मूला मिल्क या अर्द्ध–ठोस आहार दिया जाता है– मैश किया केला, सेब, कस्टर्ड, जूस, दाल का पानी, कम मसालों वाली पिसी दाल, खिचड़ी, दूध–दही, सब्जियों का जूस आदि दिया जा सकता है। बारह महीने में दांत निकलने लगते हैं तो उन्हें रोटी का टुकड़ा, बिस्कुट या फल का टुकड़ा दे सकते हैं। वहीं 2–10 साल की उम्र के बच्चों का मानसिक विकास, सोचने–समझने की क्षमता, स्मरणशक्ति, शारीरिक गतिविधियों का विकास शुरू हो जाता है। उनकी डाइट में विटामिन और मिनरल्स से भरपूर दूध और दूध से बने पदार्थ, फल–सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें शामिल करनी चाहिए। पूरे दिन में 30–35 ग्राम प्रोटीन, 20–25 ग्राम फाइबर, 15–20 ग्राम फैट देना चाहिए। मिनरल्स और विटामिन लेने बहुत जरूरी हैं। फल, सब्जी–सलाद ,एक–दो कटोरी अनाज, दाल हर मील में जरूरी है। दूध जरूर दें। वहीं 30–35 प्रतिशत कैलोरी ऑयल या घी, मक्खन, नट्स फैट से देनी चहिए।

किशोरों के लिए डाइट

किशोरों में होने वाले शारीरिक और हार्मोनल बदलावों के लिए प्रोटीन, फैट, आयरन और कैल्शियम रिच डाइट देनी जरूरी है। फैट एनर्जी प्रदान करने और ब्रेन डेवलेपमेंट में , प्रोटीन मसल्स को मजबूती प्रदान कर शारीरिक विकास में मदद करता है। इसके लिए गाजर, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां और केला, सेब व अनार जैसे फल दिए जा सकते हैं। करीब 500 मिली दूध या डेयरी प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं।

वयस्क व्यक्ति का भोजन

20 साल के बाद शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, उसे मेंटेन करने के लिए न्यूट्रीएंट्स जरूरी हैं। पुरुषों की डाइट में खास फर्क नहीं आता। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, विटामिन और मिनरल्स बढ़ाए जाते हैं। रोजाना 2–3 लीटर पानी पीना चाहिए। व्यस्क व्यक्ति की हेल्दी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स पोषक तत्व जरूर शामिल करना चाहिए। जिसमें एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, दो रोटी, एक कटोरी दही, सलाद और फल हो सकते हैं। हड्डियों और मसल्स के स्वास्थ्य के लिए डाइट में कैल्शियम–प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें– दूध और दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, राजमाह, सोयाबीन, बादाम, सफेद तिल, दालें, अंडे का सफेद भाग। रिफाइंड चीजें– मैदा, नमक और चीनी अवायड करें। ऑयली फूड या तला–भुना खाने से परहेज करें। आहार में अनसेचुरेटिड या गुड क्वालिटी हैल्दी फैट को ही शामिल करना चाहिए।

प्रशिक्षक अपने–अपने जनपदो में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर फर्स्ट रिस्पाण्डर तैयार करने का कार्य करेंगे

लखनऊ (प्रत्यूष पाण्डेय). गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० छठामील, लखनऊ में प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा संयुक्ता समद्दार ने मास्टर ट्रेनर्स पाठ्यक्रम का दीप प्रज्जवलन कर उद्घाटन किया। प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार ने अपने सम्बोधन में कहा कि नागरिक सुरक्षा मुख्यतः स्वयंसेवको का संगठन है, जो देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते है। वर्तमान परिदृश्य में नागरिक सुरक्षा की महत्ता काफी बढ़ गयी है, जिस कारण भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार नागरिक सुरक्षा के सुदृणीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि स्वयंसेवको को दिये जा रहे, इस प्रशिक्षण से विभिन्न आपदाओं में कुशलता से काम करने में सहयोग मिलेगा तथा यहाँ तैयार किये गये प्रशिक्षक अपने–अपने जनपदो में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर फर्स्ट रिस्पाण्डर तैयार करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा अभय कुमार प्रसाद द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करते हुए नागरिक सुरक्षा के समस्त पदाधिकारियों को वर्तमान परिदृश्य के चलते सजग रहने एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवको को राष्ट्र सेवा हेतु किसी भी आपदा की परिस्थिति में सामान्य जनता को प्रशिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को विशेष रूप से प्रदेश भर में नागरिक सुरक्षा विभाग खोलने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।

उत्तर प्रदेश में नेट–कास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों का पायलट प्रोजेक्ट लागू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक नगरीय परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में नेट–कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शीघ्र शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ, कानपुर नगर और उनके आस–पास के प्रमुख कस्बों में लागू किया जाएगा।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट बैठक के उपरांत बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटर लखनऊ और कानपुर नगर में 10–10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेंगे। प्रत्येक निजी ऑपरेटर केवल अपने निर्धारित मार्ग पर ही बस संचालन करेगा और उस मार्ग पर किसी अन्य निजी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करेगी।मंत्री ने बताया कि अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 12 वर्ष की होगी। इस अवधि में चयनित निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, निर्माण, आपूर्ति, अनुरक्षण और अन्य आवश्यक अवसंरचना की स्थापना की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। इसके अतिरिक्त, किराया संग्रहण की जिम्मेदारी भी निजी ऑपरेटर की होगी, जबकि किराया एवं टैरिफ शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा।मंत्री शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल परिवहन व्यवस्था का विस्तार नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से आम जनता को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी और प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर इसे अन्य नगरों और महानगरों में भी विस्तारित किया जाएगा। इस परियोजना से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। निजी ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के वित्तीय बोझ में कमी आएगी और आम जनता को बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध होंगी।मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि जनता को सुरक्षित, सुलभ, किफायती और प्रदूषण रहित परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएँ।

संक्षिप्त खबरें

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष प्रदेश स्तरीय सीनियर वर्ग महिलाध्पुरूष प्रतियोगिता का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि खेल निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार वर्ष 2025–26 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सीनियर वर्ग महिलाध्पुरूष की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वाराणसी मण्डल की टीम प्रतिभाग करेगी। खेल निदेशालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपद के खिलाड़ी सीधे मण्डल स्तर पर आयोजित चयन परीक्षण में प्रतिभाग करेंगे। वाराणसी मण्डल के बैडमिण्टन महिलाध्पुरूष का चयन परीक्षण 08 सितम्बर 2025, जिम्नास्टिक महिलाध्पुरूष– 11 सितम्बर, कबड्डी पुरूष एवं टेबल–टेनिस पुरूषध्महिला 12 सितम्बर, क्रिकेट पुरूष– 16 सितम्बर, वॉलीबाल महिला– 19 सितम्बर, एथलेटिक्स महिलाध्पुरूष एवं वॉलीबाल पुरूष– 20 सितम्बर, बॉक्सिंग पुरूष– 30 सितम्बर, कुश्ती पुरूष– 04 अक्टूबर, कबड्डी महिला– 08 अक्टूबर, जूडो महिलाध्पुरूष– 15 अक्टूबर, फुटबाल महिला– 16 अक्टूबर एवं फुटबाल पुरूष का 17 अक्टूबर, 2025 को डॉ0 सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा, वाराणसी में प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जायेगा। जनपद के इच्छुक प्रतिभागी सीधे मण्डलीय चयन परीक्षण में प्रतिभाग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला खेल कार्यालय, जौनपुर या क्षेत्रीय खेल कार्यालय, वाराणसी में सम्पर्क कर सकते हैं।

घर वापस लौट रहे बैंक मित्र से दो लाख नब्बे हजार की लूट,पुलिस जांच पड़ताल में जुटी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,।गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गद्दोपुर गांव निवासी बैंक मित्र से बदमाशों ने बुधवार की रात उस वक्त मारपीट कर ढाई लाख रुपए लूट लिए जब वह मुफ्तीगंज बाजार से अपनी दुकान बंद कर घर वापस आ रहे थे। घटना के पश्चात पहुंची पुलिस ने घायल बैंक मित्र को उपचार हेतु जौनपुर निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया तथा देर तक बदमाशों की घेरे बंदी में लगी रही परंतु लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। गद्दोपुर गांव निवासी सूर्यमणि राय मुफ्तीगंज बाजार में बैंक मित्र का कार्य करते है। 5 सितंबर को ईद उल मिलान्नबी का त्यौहार होने के कारण बैंक बंद रहेगा जिसकी वजह से उन्होंने बैंक से शाम को तीन लाख रुपए निकाले थे। लेनदेन का कार्य करने के पश्चात लगभग 10 बजे वह अपनी बाइक से घर के लिए आ रहे थे। रसूलपुर ओझयनिया गांव के पास स्थित रेलवे अंडरपास में पहले से मौजूद तीन बदमाशों ने खेत घेरने के लिए लगाई बांस बल्ली में से बांस उखाड़ कर सूर्यमणि यादव के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे असंतुलित होकर सूर्यमणि सड़क पर गिर पड़े तत्पश्चात बदमाशों ने डंडे से मारपीट कर सूर्यमणि को घायल कर दिया तथा रुपयों से भरा बैग छीनकर इटैली की तरफ फरार हो गए। सूर्यमणि राय के स्वजनों के अनुसार अनुसार बैग में दो लाख नब्बे हजार रुपए थे। सूचना पर पहुंची गौराबादशाहपुर पुलिस ने घायल बैंक मित्र को उपचार हेतु जौनपुर भिजवाया तथा लुटेरों की घेरेबंदी के लिए देर रात तक लगी

अनुप्रिया पटेल ने फिर उठाई ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा 15 लाख करने की मांग

लखनऊ, (संवाददाता)। अपना दल (एस) के मासिक बैठक में पार्टी की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने ओबीसी मंत्रालय के गठन पर भी जोर देते हुए कहा कि पिछड़े समाज का हित राजग सरकार में ही सुरक्षित है। उन्होंने योगी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए स्वतंत्र निगम का गठन करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से पार्टी द्वारा लंबे समय से की जा रही आउटसोर्सिंग के पदों की भर्ती में आरक्षण की मांग भी पूरी होगी। राजधानी के विश्वेश्वरैया सभागार में पार्टी की मासिक बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जब सत्ता में रहे तो उन्होंने ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा नहीं बढ़ाई। ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा पहले भी राजग सरकार ने ही छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की थी। अब परिस्थितयों को देखते हुए इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए बूथ मजबूत करेगी पार्टी पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेगी। पंचायत चुनाव राजग के साथ लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर बात नहीं हुई है। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि विधानसभा प्रभारी बनाए गए पदाधिकारी अपनी–अपनी विधानसभा की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। जो कमजोरी है उसे दूर किया जाए।

उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए बड़ा कदम, पर्यटन निदेशालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया एमओयू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में आज पर्यटन निदेशालय गोमतीनगर में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारतीय कलाओं, साहित्य, नृत्य, संगीत, नाटक और दृष्य कलाओं के अनुसंधान तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित है। एमओयू का उद्देश्य दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एक साझा ढांचा तैयार करना है, ताकि संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके।उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कुल 273 स्मारक और पुरास्थल संरक्षित हैं, जिनमें सोनभद्र, मीरजापुर जैसे स्थानों पर प्रागैतिहासिक से मध्यकाल तक के शैलचित्र शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत अनुसंधान, शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी और इनक्यूबेशन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।जयवीर सिंह ने कहा कि यह एमओयू शैलचित्र और पुरातत्व के क्षेत्र में अल्पकालिक शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को भी प्रमुखता देगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली मानव संस्कृति और ब्रह्माण्ड के विज्ञान के बीच अंतःविषय संबंधों का अध्ययन करता है और शोध तथा अध्ययनों के माध्यम से दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है। यह समझौता उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में अहम भूमिका निभाएगा और लोक कलाओं जैसे गीत–संगीत, नृत्य और नाटक को बढ़ावा देगा।कार्यक्रम में प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग मुकेश मेश्राम ने इस समझौता ज्ञापन की सफलता की कामना की।

संक्षिप्त खबरें

लगातार चल रहा नो हेलमेट नो फ्यूल के तहत अभियान

अयोध्या। बुधवार को भी एआरटीओ प्रवर्तनध्प्रशासन डाक्टर आर पी सिंह ने नो हेलमेट नो फ्यूल का के तहत अभियान चलाया।बताया कि यह अभियान 30 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा।नो हेलमेट न फ्यूल का उद्देश्य लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता को लागू कराना है,जिससे व्यक्ति अपनी जान बचा सके।इस मौके पर एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर आरपी सिंह के अलावा यात्री कर अधिकारी राजेश कुमार एवं यात्री कर अधिकारी रानी सेंगर उपस्थित रही।अभियान के तहत बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालकों को जहां एक तरफ जागरूक किया गया वहीं दूसरी तरफ उनके चालान भी किए गए।अभियान के दौरान बिना हेलमेट 76 चालान किया गया।

एसटीएफ टीम ने अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

अयोध्या। बुधवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के कौशलपुरी कालोनी, प्रवेश गेट के निकट, लखनऊ–अयोध्या बाइपास (निकट पैथ काइण्ड लैब के पास) से एसटीएफ टीम ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मौके पर उनके कब्जे से 34 किलोग्राम गाँजा बरामद किया।एसटीएफ के मुताबिक बाजार मे अर्न्तराष्ट्रीय उसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपये है।गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान आशीष कुमार अग्रहरि पुत्र राजेश अग्रहरि, निवासी लक्ष्मनपुरी कॉलोनी, गद्दोपुर, थाना कैण्ट,राजेश अग्रहरि पुत्र लालचन्द्र, निवासी लक्ष्मनपुरी कॉलोनी, गद्दोपुर, थाना कैण्ट के रुप मे हुई।इनके पास से टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार बरामद किया।जिसमे यह गांजा रखा गया था।टीम मे शामिल सदस्यों के मुताबिक विगत कुछ दिनों से एस०टी०एफ०, उ०प्र० को उडीसा, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी।जिसको लेकर एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों ध्टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।सीओ एसटीएफ फील्ड इकाई अयोध्या प्रमेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व मे उप निरीक्षक सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई अयोध्या की टीम जनपद अयोध्या में भ्रमणशील थी।तभी कूरियर सर्विस के माध्यम से आज भारी मात्रा में गांजे की डिलेवरी होने वाली है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा तत्काल एन०सी०बी० गोरखपुर की टीम के साथ लेकर 02 तस्करों को गिरफ्तार किया।एसटीएफ के सदस्यों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशीष अग्रहरि एवं राजेश अग्रहरि ने पूछताछ में बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है,जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है।इस गिरोह का सरगना राजेश अग्रहरि है।वही राजेश अग्रहरि द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य वह कूरियर कम्पनी के कर्मचारियों की मिली भगत से कम्पोस्ट फर्टिलाइजर ध चाय पत्ती के नाम पर उड़ीसा ध बंगाल आदि स्थानों से गांजा मंगवाता है। उक्त गांजे को वह थोक एवं फुटकर रूप में वह विभिन्न व्यक्तियों को बेंचता है।

उत्तर प्रदेश में डिजिटल एपीओ पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कैम्पा के अन्तर्गत वार्षिक प्रचालन योजना के प्रस्ताव और अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और दक्ष बनाने के उद्देश्य से आज एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डॉ. अरूण कुमार ने कार्यशाला का शुभारम्भ किया और प्रतिभागियों को आशीर्वचन दिए।डॉ. अरूण कुमार ने कहा कि कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कैम्पा की वेबसाइट और डिजिटल एपीओ पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रचालन योजना की अनुमोदन प्रक्रिया और कार्यान्वयन अधिक व्यवस्थित ढंग से होगा। उन्होंने कहा कि व्यापक जन सहयोग और जन सहभागिता से ही 'सबका साथ–सबका विकास–सबका प्रयास–सबका विश्वास' के मूलमन्त्र को आत्मसात कर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्मरण दिलाया कि 9 जुलाई 2025 को प्रदेश में एक ही दिन में 37 करोड़ से अधिक पौध रोपित किए गए थे, जो इस दिशा में सफलता का उदाहरण है।कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुनील चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय कैम्पा के मार्गदर्शन में प्रदेश में वृक्षारोपण, पौधशालाओं में सुधार, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना, मानव–वन्यजीव संघर्ष न्यून करने के लिए रेस्क्यू सेंटर की स्थापना, सोलर वाटर पम्प की स्थापना, वन क्षेत्र में गस्त और भूमि एवं जल संरक्षण कार्य जैसी विभिन्न पहलें संचालित की गई हैं।संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय कैम्पा भारत सरकार निशांत वर्मा ने कार्यशाला के उद्देश्य, पृष्ठभूमि और महत्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश स्टेट कैम्पा और वन एवं वन्यजीव विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।उत्तर प्रदेश राज्य कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.पी. सिंह ने कहा कि डिजिटल एपीओ पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रचालन योजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यों की गति और परिणामों में सुधार होगा।कार्यशाला में उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों– पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के प्रतिभागियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन भाग लिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन निगम और राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा स्थापित प्रदर्शिनियों का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और वृक्षारोपण अभियानों की सराहना की गई।इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी थे– प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्ययोजना एवं अनुश्रवण बी. प्रभाकर, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम ए. के. सिंह, सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सुशान्त शर्मा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश पी.पी. सिंह एवं अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी।कार्यशाला का आयोजन डिजिटल एपीओ पोर्टल के माध्यम से कैम्पा की वार्षिक प्रचालन योजना को सुव्यवस्थित करने, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

बुंदेलखंड और आगरा मंडल में भारी बारिश की चेतावनी, एहतियात के तौर पर इन जिलों में स्कूल बंद

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तरप्रदेश में मानसूनी बारिश बुधवार को भी जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का प्रसार मध्य भारत की ओर शिफ्ट हुआ है जिसके असर से यूपी में फिलहाल चार–पांच दिनों के लिए बारिश का दायरा सिमटेगा। मौसम विभाग की ओर से बुधवार के लिए प्रदेश के बुंदेलखंड और आगरा मंडल के 10 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। बृहस्पतिवार के लिए यूपी में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। मंगलवार को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बंगाला की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम कमजोर पड़ा है। साथ ही मानसूनी प्रसार मध्य भारत की ओर खिसका है। इसके असर से उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पहले से कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। ये ज्यादातर जिले पश्चिम यूपी के हैं। मंगलवार को भी अवध और पश्चिम यूपी के कई जिलों में छुट्टी रही है। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 3 सितंबर को कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। गौतमबुद्धनगर जनपद में संचालित सभी बोर्ड के स्कूल अत्यधिक वर्षा के कारण कल बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर बारिश को देखते हुए छुट्टी करने का निर्देश जारी किया है। जनपद के चारों ब्लॉक में परिषदीय, राजकीय,सहायता प्राप्त सीबीएसईआईसीएसई के साथ अन्य बोर्ड के नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल में बुधवार को अवकाश घोषित रहेगा।

बरेली में भारी बारिश के कारण लगातार तीसरे दिन भी स्कूल बंद

बरेली जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश और जलभराव के कारण विद्यार्थियों की।

होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी होगी भर्ती

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य सरकार होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि जल्द ही 44 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती भी होनी है। साथ ही, कंपनी कमांडर और मिनिस्टीरियल स्टाफ के रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। सूत्रों की मानें तो करीब 47 हजार पदों पर भर्तियां होनी हैं। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों होमगार्ड संगठन की समीक्षा की थी। उन्होंने होमगार्ड संगठन के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरह अलग बोर्ड गठित करने के साथ भर्ती नियमावली तैयार करने का निर्देश भी दिया था। होमगार्ड संगठन में वर्तमान में कंपनी कमांडर के 783, सहायक कंपनी कमांडर के 770, प्लाटून कमांडर के 2314 और होमगार्ड स्वयंसेवकों के 43,327 पद रिक्त हैं। इसके अलावा मिनिस्टीरियल स्टाफ के भी 109 पद रिक्त चल रहे हैं। बता दें कि पहले होमगार्ड संगठन में मंडल स्तर पर भर्तियां की जाती थी, जिसे अब बोर्ड का गठन करने के बाद लिखित परीक्षा के जरिये किया जाएगा। इसमें आपदा प्रबंधन का अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को वरीयता दी जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद बोर्ड के गठन की कवायद शुरू होगी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति विभाजन पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा तय

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देने वाला निर्णय लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति विभाजन विलेख के पंजीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा पाँच–पाँच हजार रुपये कर दी गई है।स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है ताकि संयुक्त या अविभाजित संपत्ति के सहस्वामी बिना आर्थिक बोझ महसूस किए आसानी से विभाजन विलेख का रजिस्ट्रीकरण करा सकें। उनके अनुसार, नई व्यवस्था से परिवारों में संपत्ति का सौहार्दपूर्ण बँटवारा सरल और शीघ्र हो सकेगा और साथ ही प्रदेश में संपत्ति संबंधी मुकदमों में उल्लेखनीय कमी आएगी।मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक विभाजन विलेख पर संपत्ति के मूल्य के अनुसार शुल्क देय होता था, जिससे लोग अक्सर रजिस्ट्री कराने से बचते थे। लेकिन पाँच हजार रुपये की अधिकतम सीमा तय होने के बाद बड़ी संख्या में लोग संपत्ति विभाजन के विलेख का पंजीकरण कराने के लिए आगे आएँगे। उन्होंने यह भी बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ऐसी व्यवस्था लागू है, जहाँ इस कदम से पारिवारिक विवादों का सहज समाधान हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल परिवारों में विवादों में कमी आएगी, बल्कि विभाजित संपत्ति का नामांतरण और खतौनी का अद्यतन समय पर हो सकेगा।

कंपोजिट विद्यालय धर्मसारी में लायंस क्लब 'क्षितिज' द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित

शिक्षक होता है समाज का निर्माता।

जौनपुर ब्यूरो चीफ विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 4 सितंबर 2025 को लायंस क्लब 'क्षितिज' ने वर्ष 2025–26 के लिए गोद लिए गए कंपोजिट विद्यालय धर्मसारी, करंजाकला में एक गरिमामय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायन धर्मेंद्र सेठ (पूर्व अध्यक्ष), विशिष्ट अतिथि एआरपी डॉ. सुरेश मौर्या, अटेवा ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रदीप उपाध्याय एवं लायन सुनील कन्नौजिया रहे। समारोह का उद्देश्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर लायंस क्लब 'क्षितिज' के पदाधिकारियों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश मौर्य समेत शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में अभिषेक कुमार, बबीता चौबे, ज्योति मौर्य, रश्मि यादव, नितेश सिंह, सूरज यादव एवं रीना यादव शामिल रहे। समारोह में विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक एवं छात्र–छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लायंस क्लब 'क्षितिज' के अध्यक्ष लायन अतुल सिंह, मुख्य अतिथि लायन धर्मेंद्र सेठ व अन्य सदस्यों ने विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाने हेतु विभिन्न सहयोगात्मक पहलों की घोषणा भी की। समारोह की अध्यक्षता व संचालन क्लब अध्यक्ष लायन अतुल सिंह ने किया, जबकि आभार ज्ञापन कोषाध्यक्ष लायन सुनील कन्नौजिया ने व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मंगली पुरवा फाटक स्थित श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन भावपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और "गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु..." श्लोक के साथ हुई, जिससे पूरा वातावरण गुरु भक्ति से ओतप्रोत हो गया।

समारोह में विद्यालय में 10 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इनमें प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, शिक्षिकाएं मंशा वाजपेई, आरती वर्मा, राजेश कुमारी गुप्ता, विनीता त्रिवेदी, अर्पिता सिंह और शिक्षक अशोक गुप्ता व राम प्रकाश पांडे शामिल रहे। इनके समर्पण और शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना की गई। साथ ही, 6 वर्षों से अधिक समय से विद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षकों दृ सोनी तिवारी, प्रज्ञा त्रिवेदी, कविता गुप्ता, भूमिका सिंह, अपर्णा श्रीवास्तव, स्वाति अवस्थी ,सोनम शुक्ला, कोमल यादव और आरती मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अखिलेश सिंह ने शिक्षकों की भूमिका को समाज निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के जीवन में संस्कार और विकास की नींव रखते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक मुकेश सिंह ने सभी शिक्षकों का आभार प्रकट किया और इसी तरह अच्छी शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कारित व अनुशासित बनाने में सहयोग की अपील की।

संक्षिप्त खबरें

गणेश पूजा व बरावफात जुलूस को लेकर पुलिस कर रही पैदल गस्त

अयोध्या।बारावफात व गणेश पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौक चौकस दिखाई दे रहा है। कोतवाली नगर से लेकर सभी थानों पर संबंधित सीओ व द्वारा संबद्ध व्यक्तियों,धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक की जा रही है वहीं अराजक तत्वों से निपटने के लिए इन थाना क्षेत्र में संबंधित पुलिसकर्मियों द्वारा पैदल गस्त भी किया जा रहा है।जिले के कोतवाली नगर के अलावा थाना कैंट पूरा कलंदर, हैदरगंज, बीकापुर, महाराजगंज,गोसाईगंज के अलावा सभी थाना क्षेत्रों मे पुलिस कर्मियों द्वारा पैदल गस्त किया जा रहा है इस दौरान जहां एक ओर शाम को गणेश पूजन के दौरान निकलने वाले श्रद्धालुओं तथा बारावफात जुलूस के समय निकलने वाले लोगों को सुरक्षा के प्रति एहसास दिला रहे हैं।पुलिस कर्मियों ने अराजक तत्वों को चेतावनी भरे शब्दों में भी कहा कि अगर इस दौरान कोई भी अराजक तत्व किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए पाया गया तो पुलिस उस शख्ति से निपटेगी।वहीं महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला भी अपने टीम के साथ नगर के अधिकतर गणेश प्रतिमा लगे पंडालो पर जाकर निरीक्षण किया और वहां के पदाधिकारी को अस्वस्थ किया कि पुलिस आपकी सुरक्षा में है।उन्होंने बताया कि अराजक तत्वों से निपटने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तो रहेगी ही इसके साथ ही साथ सादे पोशाक मे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी।

भरतपुर व ताहिरपुर विद्यालय बने शिक्षा के आदर्श

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद के परिषदीय विद्यालय अब शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सिकरारा ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय भरतपुर और प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर अपने–अपने संसाधनों, अनुशासन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दम पर आदर्श बन चुके हैं। कंपोजिट विद्यालय भरतपुर में कक्षा–कक्ष रूपांतरण, कंप्यूटर व प्रिंटर युक्त ऑफिस, स्मार्ट बोर्ड, टीवी, ब्लूटूथ, प्रोजेक्टर, माइक–स्पीकर, मॉर्निंग असेम्बली माइक, सीसीटीवी कैमरा व वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक कक्षा डेस्क–बेंच से सुसज्जित है तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है। विद्यालय को 19 पैरामीटर पर संतृप्त घोषित किया गया है। यहां निःशुल्क शिक्षा के साथ कंप्यूटर शिक्षा व वीरांगना लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शून्य निवेश से बनी लाइब्रेरी, डीलएमएस और साफ–सुथरे शौचालय इसकी विशेषता हैं। विद्यालय की इंचार्ज हेड टीचर संगीता सिंह ने बताया कि इन सभी कार्यों की सफलता सहायक अध्यापक राजू सिंह के सहयोग से संभव हुई है। वहीं, प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर आधुनिक संसाधनों से लैस होकर गुणवत्तापरक शिक्षा का आदर्श बन चुका है। यहां सभी कक्षाओं में स्मार्ट टीवी व टीएलएम उपलब्ध हैं। 7 जून 2022 को जनपद का पहला डिस्कवरी लैब यहीं स्थापित हुआ, जिसमें विज्ञान के 150 से अधिक उपकरण हैं। प्रधानाध्यापक डॉ. अमित सिंह के नेतृत्व में विद्यालय 2018 में 63 बच्चों से बढ़कर आज 262 बच्चों तक पहुँच गया है।

अगली बैठक में योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाए – कुलपति

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 29 वां दीक्षांत समारोह आगामी 6 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस संबंध में कुलपति सभागार में गुरुवार को कुलपति प्रो. वंदना सिंह की अध्यक्षता में तैयारी बैठक हुई। बैठक में समिति के संयोजकों से बिंदुवार चर्चा की गई। कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने 53 समितियों के संयोजकों के साथ चर्चा की। कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह की तैयारियों में सभी निर्देशों का प्राथमिकता से पालन होगा। अगली बैठक में योजनाओं को मूर्तरूप दे दिया जाए इस अवसर पर समारोह की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए संयोजकों से सुझाव भी लिए गए।

बैठक का संचालन कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रो. मानस पांडेय, प्रो. अविनाश पाथर्डीकर, प्रो. अजय द्विवेदी, छात्र अधिष्ठाता प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. राकेश यादव, प्रो. गिरधर मिश्र, डॉ. मनीष गुप्ता, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. अनु त्यागी, डॉ. मंगला प्रसाद यादव, दिग्विजय मिश्र, राजन तिवारी, उपकुलसचिव अमृतलाल, बबिता सिंह, अजीत प्रताप सिंह, डॉ. राजेश सिंह, सुशील प्रजापति सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी समितियों के संयोजक उपस्थित रहे।

'विवेकानंद सभागार में हुई पीस कमेटी की बैठक'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता मे आगामी त्योहारों को सकुशल शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आहूत की गयी। उन्होंने ने कहा कि वर्तमान में श्री गणेश चतुर्थी इसके साथ ही 05 सितम्बर 2025 को स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों द्वारा बारावफात का त्योहार भी मनाया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग मिल जुल कर त्योहार मनाएं। उन्होंने कहा कि जनपद मे कोई भी नई परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। बारावफात का जुलूस एक दूसरे की भावनाओं का आदर एवं सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला जाए। उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बारावफात के दृष्टिगत संबंधित विभागीय अधिकारी साफ–सफाई की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, जल निकासी आदि की व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपस्थित आयोजकों से कहा कि लोग सभी त्योहार आपसी सद्भाव, भाईचारे व प्रेम से मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी छोटी से छोटी घटना की जानकारी प्रशासन व पुलिस को दी जाए साथ ही सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की जानकारी होने पर भी तत्काल प्रशासन व पुलिस को अवगत कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि अस्पतालों मे दवाइयों और डाक्टरों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जायें। उन्होंने जुलूस के रास्तों का भी स्थलीय निरीक्षण कर ठीक करा लेने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने समस्त ईओ को निर्देशित किया कि बिजली आपूर्ति निर्बाध रखा जाये। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखा जाये। बिजली के जर्जर पोल व तारों को बदला जाये। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कहा कि लाउडस्पीकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। रात्रि में लाउडस्पीकर न बजाया जाये।

संक्षिप्त खबरें

शैक्षणिक विकास मे सराहनीय भूमिका निभा रहे है राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित डॉ अंबिकेश त्रिपाठी

अयोध्या। कंपोजित विद्यालय तमकीनगंज विकासखंड तारुन के राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक डॉ अंबिकेश त्रिपाठी द्वारा बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है।बताया कि छात्रों को छोटे–छोटे नवाचारों के माध्यम से बहुत ही सरल एवं सहज रूप से गणित एवं विज्ञान शिक्षण का कार्य कराया जा है जिससे बच्चे बहुत ही सुगमता से गणित सीखने का आनंद ले रहे है।वही शासन के मंशानुरुप छात्रों का पढने मे मन लग रहा है।मालूम हो कि डॉ अंबिकेश त्रिपाठी द्वारा भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित पांच टेलीविजन शैक्षिक चौनलों के प्रसारण हेतु प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय पर रोचक ढंग से वीडियो का निर्माण एनसीईआरटी लखनऊ के द्वारा कराया गया है।जिससे प्रदेश के सभी बच्चे लाभान्वित होंगे।अंबिकेश त्रिपाठी जी द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक एवं आनंदपूर्ण बनाते हुए बच्चों को सिखाया जाता है। वे स्मार्ट क्लास के माध्यम से जटिल विषय को भी बहुत ही सरल ढंग से बच्चों को सिखा भी रहे है।

कार्यालय कैम्पस में रोजगार मेला का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर निदेशक, सेवायोजन उ०प्र०, लखनऊ एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला सेवायोजन कार्यालय कैम्पस जौनपुर में 08 सितम्बर 2025 को प्रातः 10:00 बजे रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों में रोजगार हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, जिसकी शैक्षिक योग्यताः हाईस्कूल, इण्टर, आई०टी०आई० एवं स्नातक उत्तीर्ण आयुसीमा 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों को कैम्पस सलेक्शन करेंगी। अभ्यर्थी अपने योग्यतानुसार प्रतिभाग करते हुए, पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्राप्त करें। जिला सेवायोजन अधिकारी जय प्रकाश पासवान ने बताया की रोजगार मेला में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति आई०डी०प्रूफ बायोडाटा सहित प्रतिभाग करेंगे एवं सेवायोजन वेब पोर्टल– "ूूूण्तवरहंतेंदहंउण्नचण्हवअण्पद" के माध्यम से पंजीकरण कर अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की है।

बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए शिक्षक अपना योगदान देते रहें : अनुनय झा

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

जनपदीय शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार, कलेक्ट्रेट, हरदोई में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अनुनय झा तथा विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा रहे। कार्यक्रम का प्रारम्भ सरस्वती वंदना से हुआ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने अपने स्वागत उद्बोधन में सभी शिक्षकों का अभिनन्दन किया एवं सभी को शिक्षक दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। जिलाधिकारी ने उपस्थित शिक्षकों के विद्यालयों में योगदान की सराहना की एवं आह्वान किया कि बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए अपना योगदान देते रहें।

मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर जनपद के उत्कृष्ट 100 शिक्षक/शिक्षा मित्र/अनुदेशकों को प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह, डायरी व पेन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य कराने वाले 5 ग्राम प्रधानों व बच्चों की नियमित उपस्थिति कराने वाले 5 अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षिका मंजू वर्मा, ग्राम प्रधान चन्द्र शेखर आजाद तथा अभिभावक विपिन कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डायट योगेन्द्र सिंह ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए आभार ज्ञापन किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह का संचालन एसआरजी आशीष कुमार मिश्र ने किया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक प्रशिक्षण दिलीप कुमार शुक्ल, अभय सिंह, दिव्या सिंह, आशीष राज, अनिल कुमार, विवेक मिश्र आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम व भारी संख्या में शिक्षक गण उपस्थित रहे।

जीवन को सही दिशा देता है शिक्षक - प्रो.अजय प्रताप सिंह

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान लैब में गुरुवार को शिक्षक दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक हुआ। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में कविताएं और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शिक्षकों ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए विचार रखे। व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष ने कहा कि "शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन में सही दिशा दिखाने वाला पथप्रदर्शक होता है। विद्यार्थी सदैव प्रश्न पूछें और सीखने की जिज्ञासा जीवित रखें।" संकाय अध्यक्ष प्रो. मनोज मिश्र ने कहा कि "शिक्षक का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों का विकास करना भी है। यही शिक्षा की पूर्णता है।" जनसंचार विभाग के डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि "शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर समाज को नई दिशा दे सकते हैं।" व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग की डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव ने कहा कि "गुरु–शिष्य का संबंध सदियों से भारतीय संस्कृति की आत्मा रहा है। विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन और परिश्रम को अपनाएं।" डॉ. मनोज पांडे ने कहा कि "शिक्षक दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। शिक्षक तभी सफल हैं जब उनके विद्यार्थी समाज में जिम्मेदार भूमिका निभाएं।" डॉ. अनु त्यागी ने कहा कि "विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करने के लिए शिक्षा को साधन बनाएं। शिक्षकों का सम्मान ज्ञान की रोशनी को और प्रखर करता है।" इस कार्यक्रम में सुमित सिंह, शैम्पी अग्रहरि, शिवकांत ओझा, अमन कौनौजिया, उमम आदि ने अपनी प्रस्तुति दी, इस अवसर पर डॉ चंदन सिंह डॉ. अमित मिश्र, डॉ सुरेंद्र कुमार, अर्पित समेत सभी विद्यार्थियों ने शिक्षकों से प्रेरणा ली। कार्यक्रम का संचालन मनोविज्ञान विभाग की छात्रा प्रीति सिंह ने किया

'धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' कस्बे के सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज में देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम कालेज के प्रधानाचार्य डॉ वेदप्रकाश द्विवेदी ने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य स्व0 बृजवल्लभ सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर दोनों महान विभूतियों को नमन कर याद किया। तत्पश्चात मौजूद सभी शिक्षकध्शिक्षिकाओं ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कालेज की छात्राओं में अंशिका, अनम और तारा बानो ने अपनी –अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि एक शिक्षक हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। कालेज के प्रधानाचार्य जी ने तीनों छात्राओं को धन्यवाद देते हुए शिक्षक दिवस की महत्ता एवं गुरु शिष्य के रिश्तों का संक्षेप में व्याख्यान किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ वीपी द्विवेदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत में शिक्षक दिवस का यह खास दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने गुरु शब्द को संसार में सबसे बड़ा बताया और कहा कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाया गया या जो कुछ भी हम जानते हैं, अपने गुरुओं की बजह से ही जानते हैं। अगर शिक्षक न होते तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत न होती। उन्होंने डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन विचारक,राजनेता, शिक्षाविद,महान दार्शनिक एवं राष्ट्रपति के साथ–साथ एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। जिन्होंने भारत की शिक्षा और दर्शन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में एक शिक्षक की बहुत अहमियत होती है। माता–पिता के बाद शिक्षक ही हमारे जीवन को निखारने और एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।